International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 5, May- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

भारत की परमाणु नीति–

डॉ. प्रशांत पँवार
वरिष्ठ व्याख्याता (राजनीति विज्ञान)
राज. आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जोधपुर (राज.)

1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय विश्व राजनीति दो गुटों–अमेरिकी और सोवियत गुट में बंट चुकी थी और शीत युद्ध का आरम्भ हो गया था। ऐसी विषम अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में अन्तरिम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने 7 सितम्बर 1946 को अपने रेडियो भाषण में घोषणा की कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, भारत की स्वतंत्र नीति के साथ हिस्सा लेगा। भारत शक्ति संघर्ष में फंसने की इच्छा नहीं रखता और गुटबाजी से अलग रहेगा।[1] भारत की इसी नीति के अनुरूप भारत में संविधान के भाग–4 में नीति निदेशक तत्वों वाले अध्याय में अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली विदेश नीति का भी प्रतिपादन किया गया। भारत के राष्ट्रीय हितों में अभिवृद्धि करने और विश्व राजनीति में सम्मानजनक स्थान बनाने के लिए नेहरू प्रशासन ने परमाणु तकनीक के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जो आगे सभी सरकारों में लगातार चलता रहा। संक्षेप में भारत के परमाणु कार्यक्रम का इतिहास इस प्रकार है–

- 3 अगस्त 1948 में होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में **परमाणु ऊर्जा आयोग** की मुम्बई में स्थापना।
- 20 जनवरी 1957 को एशिया का प्रथम परमाणु भट्टी ब्रिटेन के सहयोग से मुम्बई के पूर्वी छोर में **अप्सरा** के नाम से स्थापित की गई।[2]

[1] प्रशांत पंवार : **भारत की विदेश नीति और पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध** (2017) अरिहंत प्रकाशन, जोधपुर पृष्ठ 18
[2] barc.gov.in

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 5, May- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

- राष्ट्रमण्डल देशों के आपसी सहयोग पर बने **कोलोम्बो प्लान** (1951) के अन्तर्गत कनाडा–भारत ने 28 अप्रेल 1956 को कनाडा–भारत कोलोम्बो प्लान एटोमिक रिएक्टर प्रोजेक्ट पर समझौता किया गया। कनाडा के सहयोग से भारत की दूसरी परमाणु भट्टी **साइरस** नाम से ट्रोम्बे में 1960 में स्थापित की गई।
- इनके बाद 1961 में **जरलीना**, 1985 में ध्रुव, 1972 में **पूर्णिमा–I**, 1984 में **पूर्णिमा– II,** 1990 में **पूर्णिमा–III** और 2010 में थर्मल रिएक्टर AHWR-CF आरम्भ किया गया। इनके अलावा इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र कल्पक्कम (तमिलनाडु) में भी परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं।

भारत ने स्वतंत्रता के बाद से ही परमाणु प्रौद्योगिकी में शांतिपूर्ण उपयोग–ऊर्जा, विद्युत उत्पादन, समुद्र अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान, चिकित्सा विज्ञान इत्यादि को ही ध्येय बनाकर अपना परमाणु विज्ञान कार्यक्रम आरम्भ किया। **भारत 1963 की आंशिक अणु अप्रसार संधि (PTBT) पर हस्ताक्षर करने में अग्रणी देश था।** भारत की नीति में परिवर्तन 1962 में चीन युद्ध और 1964 में चीन के परमाणु परीक्षण के पश्चात आया और भारत के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए एवं सम्भावित परमाणु हमले या हमले की धमकी की ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए भारत ने 1968 की अणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया जिस पर वह आज भी कायम है। 1960 के दशक के अन्त और 1970 के दशक के आरम्भ में वर्षों में भारत ने परमाणु हथियार बनाने के दिशा में प्रयास तेज कर दिये। इसी का परिणाम सामने आया और भारत ने 18 जून 1974 को **ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन हैप्पी कृष्णा** के नाम से अपने प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण (राजस्थान) में कर दिये। विश्व के पांच वीटो पॉवर वाले देशों के बाद भारत वह प्रथम देश बना जिसने परमाणु परीक्षण किये। बुद्ध और कृष्ण के नाम पर अपने परीक्षणों का नाम रखकर भारत ने विश्व को यह संकेत दिया कि यह परीक्षण विश्व शांति और भारत की सुरक्षा के लिए किये गए हैं। इन परीक्षणों

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 5, May- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

के लम्बे अन्तराल के बाद भारत ने पोखरण में ही **ऑपरेशन शक्ति** के नाम से 11 और 13 मई 1998 को पांच भूमिगत परमाणु विस्फोट किये जिनमें हाइड्रोजन बम का परीक्षण भी शामिल था। इन परीक्षणों में बाद भारत सरकार ने आगे भविष्य में परीक्षणों पर स्वघोषित रोक लगा दी क्योंकि अब इन परीक्षणों के बाद भारत ने कम्प्यूटर पर ही टेस्टिंग में महारथ हासिल कर ली थी अतः 1998 के बाद आज तक पुनः भूमिगत परमाणु परीक्षण नहीं किये गए हैं। 4 जनवरी 2003 को भारत सरकार ने अपनी परमाणु नीति को पहली बार जारी किया जो कि इस प्रकार है–[3]

1. भारत की परमाणु नीति न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता के विकास एवं संरक्षण के लिए है।
2. भारत परमाणु हथियारों का **प्रथम प्रयोग नहीं करेगा** लेकिन यह सिद्धांत तब लागू नहीं होगा जब भारत पर परमाणु हमला किया जाए।
3. जवाबी उत्तर में भारत द्वारा किया गया परमाणु हथियार प्रयोग अत्यन्त व्यापक और अभूतपूर्व होगा।
4. परमाणु प्रहार करने का निर्णय एक नाभिकीय कमान प्राधिकरण के अन्तर्गत नागरिक–राजनीतिक नेतृत्व द्वारा किया जाएगा।
5. परमाणु हथियार विहिन देशों पर परमाणु शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
6. यदि भारत या उसके सशस्त्र बलों पर कहीं पर भी जैविक अथवा रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया जाए तो भारत भी नाभिकीय हथियारों द्वारा उसका प्रत्युत्तर देगा।
7. परमाणु हथियारों के निर्यात, मिसाइलों से सम्बन्धित सामग्री एवं तकनीकी के अप्रसार को लेकर जारी विखण्डनीय पदार्थ नियंत्रण संधि की वार्ताओं में भारत भाग लेता रहेगा और आगे और परीक्षणों पर अस्थायी प्रतिबंध जारी रहेगा।

[3] Pib.gov.in PMO 4 Jan. 2003

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 5, May- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

8. भारत परमाणु हथियार मुक्त विश्व के लिए वचनबद्ध है लेकिन ऐसा सम्पूर्ण वैश्विक, प्रमाणित एवं भेदभाव रहित होना चाहिए।

3. नाभिकीय कमान प्राधिकरण में एक राजनीतिक परिषद और अधिशाषी परिषद होगी। राजनीति के परिषद के चेयरमैन प्रधानमंत्री होगें। यही निकाय परमाणु हथियारों के प्रयोग के लिए प्राधिकृत है।

4. अधिशाषी परिषद के चेयरमैन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होगें। यह परिषद नाभिकीय कमान प्राधिकरण को निर्णय लेने में सहायता प्रदान करेगी और राजनीतिक परिषद के निर्णयों को क्रियानिवत करेगी।

5. भारत की परमाणु नीति पर कार्य करने के लिए 4 जनवरी 2003 को सुरक्षा पर मंत्रिमण्डलीय कमेटी (CCS) का गठन किया गया जिसे नाभिकीय कमान प्राधिकरण की संरचना और इस पर नियंत्रण को अवलोकित करने का अधिकार दिया गया।

इस प्रकार संक्षेप में भारत की परमाणु नीति इस प्रकार है–

- भारत परमाणु शक्ति बना इसे पीछे भूमण्डलीय वास्तविकता है कि भारत चारों तरफ से परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों चीन, पाकिस्तान और हिन्द महासागर में अमेरिका के नौसैनिक परमाणु शस्त्रों के अड्डे **डियागो गार्शिया** से घिरा हुआ है। **1998 में परमाणु परीक्षणों के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा–"अमेरिका की तरह हम भी अपने हितों की रक्षा में आकांक्षी है। उसे यह बात समझनी चाहिए।"**[4]
- भारत ने परमाणु महाशक्ति बनने के लिए लगभग 5 दशकों तक इंतजार किया और भारत में वैज्ञानिकों ने इस दिशा में बहुत अधिक मेहनत की जिसे भारत गंवाना नहीं चाहता था। **1974 के पोखरण–I के अगुआ वैज्ञानिक राजा रमन्ना कहते हैं– "आप वैज्ञानिकों को 24 साल तक अधर में लटकाये नहीं रख सकते। वे गायब हो**

[4] इण्डिया टुडे, 27 मई 1998

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 5, May- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

जायेंगे।''[5] इसी प्रकार पोखरण –I के मुख्य उन्नायक होगी सेठना ने टिप्पणी की– ''परमाणु हथियारों की प्रौद्योगिकी विकसित करने के मामले में पहले रेंगना पड़ता है फिर उठकर लड़खड़ाते हुए चलना और अन्त में दौड़ने की कुवत आती है। अब हम दौड़ने लगे हैं।[6]

- ❖ अणु अप्रसार संधि (NPT) और व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) अन्यायपूर्ण और विभेदमूलक है। इन संधियों में परमाणु हथियारों के खात्मे की कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गई है साथ ही इन संधियों में कुछ ऐसे प्रावधान जान–बूझकर रखे गए हैं जिनके कारण परमाणु शक्ति विहिन देश सदा के लिए इनसे वंचित हो जाएं, इससे परमाणु क्लब देशों द्वारा गैर परमाणु शक्ति वाले देशों पर ब्लैकमेलिंग का खतरा बढ़ जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हाराव ने पद पर रहते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा था –

''हम NPT जैसी किसी चीज पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते जिसे हम भेदभावपूर्ण मानते हैं।[7] इन्हीं कारणों से भारत ने NPT के प्रावधानों के अनुसार 25 वर्ष बाद आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में न्यूयार्क सम्मेलन का 1995 में बहिष्कार कर दिया। इसी प्रकार भारत के आक्षेपों को दरकिनार करते हुए जब 10 सितम्बर 1996 को CTBT हस्ताक्षर के लिए खोली गई तब भी भारत ने इस पर हस्ताक्षर करने से साफ इन्कार कर दिया। जेनेवा में इस बारे में चल रहे 61 देशों के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल की अध्यक्षता **सुश्री अरूंधती घोष ने स्पष्ट कहा कि ''भारत ऐसी CTBT पर न तो अभी और न ही कभी हस्ताक्षर करेगा।**[8] इसी प्रकार विदेश मंत्री इन्द्र कुमार गुजराल ने CTBT को एक

[5] इण्डिया टुडे 24 जून, 1998
[6] वही
[7] Voanews.com 26 Oct. 2009
[8] इण्डियन एक्सप्रेस – 28 जुलाई 2016

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 5, May- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

ढ़ोंग या नाटक की संज्ञा दी।[9] NPT और CTBT पर भारत के आक्षेपों पर DRDO के पूर्व निदेशक जसजीत सिंह की यह टिप्पणी भी गौर करने योग्य है–**''परमाणु शक्ति वाले देश खुद तो परमाणु छतरी की छाया में बैठे हैं और हमसे कहते हैं कि धूप में बैठें।**[10]

- भारत ने अपनी परमाणु नीति में इस बात पर जोर दिया है कि वह परमाणु हथियारों का प्रथम प्रयोग नहीं करेगा (No First Use Policy) लेकिन पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की घटनाओं के बाद हाल ही के वर्षों में भारत की इस नीति में बदलाव की बातें आ रही हैं। रक्षामंत्री मनोहर परिकर ने परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने की नीति पर अपनी बात रखते हुए कहा था कि भारत को अपने परमाणु सिद्धांत के बारे में दोबारा विचार करना चाहिए।[11] परिकर के बाद पूर्व विदेश सचिव शिवशंकर मेनन ने भी माना कि किसी परमाणु ताकत सम्पन्न देश के खिलाफ भारत न्यूक्लियर हथियार कब इस्तेमाल करेगा, इससे जुड़ी स्थितियां साफ नहीं हैं।[12] विश्व प्रसिद्ध मेसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) के विद्वान विपिन नारंग ने वाशिंगटन में आयोजित इन्टरनेशनल न्यूक्लियर पॉलिसी कांफ्रेंस में अपनी राय रखी। नारंग के मुताबिक भारत परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ी ''नो फर्स्ट यूज पॉलिसी'' को छोड़ सकता है, अगर उसे लगता है कि पाकिस्तान उसके खिलाफ किसी भी तरह का न्यूक्लियर हमला करने की योजना बना रहा है तो वह पहले ही परमाणु जंग छेड़ सकता है।[13]
- भारत इसलिए भी परमाणु हथियार सम्पन्न देश बना क्योंकि उसकी सुरक्षा को पाकिस्तान से ज्यादा खतरा चीन से है। सैन्य शक्ति में चीन भारत से बहुत आगे रहा है, इसके पास बड़ी सशस्त्र सेनाएं, अधिक और बेहतर परमाणु हथियार है, वह भारत

[9] द न्यूयार्क टाइम्स 26 अगस्त 1996
[10] इंडिया टुडे 3 जून, 1998
[11] जी न्यूज हिन्दी, 2 अप्रेल, 2017
[12] वही
[13] वही

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 5, May- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

की तुलना में बहुत तेज गति से अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण कर रहा है, खासकर साइबर और अंतरिक्ष में।[14] SIPRI की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार चीन का सैन्य बजट लगभग 215 मिलियन डॉलर जबकि भारत का केवल 51.3 मिलियन डॉलर है जो चीन के सैन्य बजट के एक चौथाई से कम है।[15] इसके साथ ही चीन भारत को चारों ओर से घेरने के लिए **''स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स'' (मोतियों की माला)** नीति पर भी तेजी से कार्य कर रहा है। इसके तहत चीन बंगाल की खाड़ी, हिन्द महासागर और अरब सागर में भारत को चारों ओर से घेरने के लिए नौसैनिक अड्डे बना रहा है। अपनी इसी महत्वाकांक्षी योजना के तहत चीन म्यांमार के सितवे बन्दरगाह, बांग्लादेश के चटगांव बन्दरगाह, श्रीलंका के हम्बनटोटा बन्दरगाह, मालदीव के मराओ द्वीपीय बन्दरगाह एवं पाकिस्तान के ग्वादर बन्दरगाह को अपने सामरिक हितों के अनुकूल विकसित कर रहा है।[16] चीन की इस नीति को काउण्टर करने के लिए मोदी सरकार ने **''नेकलेस ऑफ डायमण्ड्स'' (हीरों का हार) रणनीति** पर तेजी से कार्य आरम्भ कर दिया है जिसके तहत हिन्द महासागर में भारत की पकड़ मजबूत रखने के लिए भारत में इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। नेकलेस ऑफ डायमण्ड्स रणनीति को मूर्त रूप देने के लिए भारत ने चांगी बन्दरगाह सिंगापुर, चाबहार बन्दरगाह ईरान, अजंम्पशन बन्दरगाह सेसेल्स, साबांग बन्दरगाह इण्डोनेशिया और डुकम बन्दरगाह ओमान में अपनी सैन्य पहुंच सम्बन्धी समझौते किये हैं। इसके अलावा चीन की क्षेत्र में बढ़त को रोकने के लिए भारत ने मंगोलिया, जापान, वियतनाम और मध्य एशिया के अनेक देशों के साथ आर्थिक–सामरिक सहयोग समझौते भी सम्पन्न किए हैं।

[14] इण्डियन डिफेंस रिव्यू 10 अगस्त 2016
[15] वही
[16] One.com 29 July 2017

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 5, May- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

- भारत की परमाणु नीति इस बात पर भी टिकी हुई है कि वह परमाणु निःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में आज भी **राजीव गांधी योजना** पर टिका हुआ है जिसमें व्यापक और समयबद्ध सम्पूर्ण परमाणु निःशस्त्रीकरण के लिए आह्वान किया गया था।[17]
- भारत परमाणु प्रौद्योगिकी का प्रयोग शांतिपूर्ण और नागरिक उद्देश्यों के लिए करेगा, इसके लिए भारत ने बार–बार अपनी वचनबद्धता दोहराई है। **विद्युत उत्पादन, ऊर्जा, चिकित्सा, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, समुद्री अनुसंधान, अंतरिक्ष शोध इत्यादि क्षेत्रों में परमाणु तकनीकी के प्रयोग को लेकर भारत ने अनेक देशों के साथ नागरिक परमाणु समझौते सम्पन्न किए हैं।** इनमें अमेरिका के साथ 2007 में किया गया **123 समझौता**, इसके बाद 2010 में भारत–फ्रांस के बीच परमाणु सहयोग समझौता हुआ जिसके तहत महाराष्ट्र के जैतापुर में बनने वाले परमाणु संयंत्र के लिए यूरोपीय प्रेशराइज्ड रिएक्टर लगाने के लिए भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड और फ्रांसीसी कम्पनी अरेवा के बीच बुनियादी समझौते पर हस्ताक्षर हुए।[18] वर्ष 2014 में भारत एवं आस्ट्रेलिया के बीच असैन्य परमाणु समझौता हुआ जिससे आस्ट्रेलिया अब भारत को यूरेनियम की आपूर्ति कर सकेगा।[19] वर्ष 2016 में राज्यसभा में उठाये गए एक अतारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए विदेश राज्यमंत्री एम.जे. अकबर ने स्पष्ट किया कि निम्न देशों के साथ भारत ने असैन्य परमाणु समझौते सम्पन्न किये है[20]–

संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, नामीबिया, कनाडा, अर्जेण्टीना, कजाकिस्तान, कोरिया गणराज्य, चेक गणराज्य, आस्ट्रेलिया, श्रीलंका, यूनाइटेड किंग्डम, मंगोलिया एवं जापान के साथ नागरिक उद्देश्यों के लिए परमाणु समझौते सम्पन्न किए गए हैं।

[17] The oxford Handbook of Indian Foreign Policy, 10 Dec. 2015 P. 650-662
[18] B.B.C. 6 Dec. 2010
[19] आज तक 6 सितम्बर, 2014
[20] विदेश मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट 11 अगस्त 2016

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 5, May- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

❖ भारत के नाभिकीय शस्त्रागार एक नाभिकीय कमान प्राधिकरण के अन्तर्गत नागरिक अधिकार और नियंत्रण में है और भारत का प्रधानमंत्री अकेले परमाणु हमले का निर्णय नहीं ले सकता, वह ऐसा सुरक्षा मामलों की केबिनेट समिति, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टॉफ कमेटी से प्रापत सलाह के बाद ही कर सकेगा।

2018 में भारत सहित वैश्विक परमाणु क्लब की तुलनात्मक सारणी[21]–

क्र.सं.	देश	तैनात परमाणु हथियार	अन्य परमाणु हथियार	कुल परमाणु हथियार
1	संयुक्त राज्य अमेरिका	1750	4700	6450
2	रूस	1600	5250	6850
3	यूनाइटेड किंग्डम	120	95	215
4	फ्रांस	280	20	300
5	चीन	–	280	280
6	भारत	–	130–140	130–140
7	पाकिस्तान	–	140–150	140–150
8	इजराइल	–	80	80
9	उत्तर कोरिया	–	10–20	10–10
	कुल योग	**3750**	**10715**	**14465**

उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट है कि भारत की परमाणु नीति उसके राष्ट्रीय हितों और वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों पर आधारित है। इस सम्बन्ध में अटलबिहारी वाजपेयी का यह कथन गौर करने योग्य है कि– ''इस सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता कि भारत परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र है। यह दर्जा न तो हमने किसी से माँगा है और न ही किसी ने हमें यह प्रदान

[21] SIPRI Year Book, 2018

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 5, May- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

किया है। देश को यह हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की देन है।''[22] भारत की परमाणु नीति का एक राज्य में ही उपसंहार करना हो तो वह शब्द है– ''बुद्ध मुस्कुराये'' यानि भारत का परमाणु बम शांति और सुरक्षा के लिए है, युद्ध एवं उन्माद के लिए नहीं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइलमैन के नाम से प्रसिद्ध डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के शब्दों में– **''अग्नि मिसाइल नाभिकीय हथियार ले जाने में सक्षम है पर समय आने पर यह फूल भी ले जा सकती है।''[23]**

[22] इण्डिया टुडे, 24 जून, 1998
[23] इण्डिया टुडे 27 मई 1998